'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि- 31 जनवरी, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 5 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 जनवरी, 2013

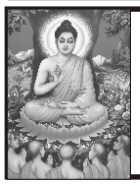

इच्छा ही सब दुःखों का मूल है।

-गौतम बुद्ध

भव्य रुप से मनाया गया डॉ. उदित राज का जन्मदिन

मुस्तफाबाद से चौधरी रवीन्द्र सिंह एवं करावल नगर से जितेन्द्र बंसल विधान सभा प्रत्याशी घोषित किए गए

सी. एल. मौर्य

26 जनवरी को मयूर गार्डन, 100 फुटा रोड, करावल नगर थाने के पास, मुस्तफाबाद विधान सभा, उत्तरी–पूर्वी दिल्ली में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज का जन्मदिन 'जस्टिस डे' के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन जस्टिस पार्टी की दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों, श्री सुरेश दीवान – प्रभारी, चौ0 रवीन्द्र सिंह – अध्यक्ष, मास्टर इन्द्रजीत सिंह – महासचिव, श्री कालीचरन नेताजी – सचिव, श्री प्रेम चंद प्रजापति – सचिव, श्री जितेन्द्र बंसल – जिलाध्यक्ष, उत्तरी–पूर्वी दिल्ली, द्वारा किया गया। प्रातः 11:00 बजे से ही जन्मदिवस समारोह में दिल्ली के कोने–कोने से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल भर गया। लगभग 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर डॉ0 उदित राज का, पत्नी सीमा राज, बेटे अभिराज व बेटी सावेरी का परिवार के साथ आगमन हुआ और डॉ0 उदित राज – जिन्दाबाद व तालियों की गड़गड़ाहट एवं संगीत के माध्यम से उनका स्वागत हुआ और सम्पूर्ण गुर्जर समाज व अन्य समाज के गणमान्य अतिथियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देने वालों में प्रमुख थे सर्वश्री चौधरी नरेन्द्र सिंह, चौधरी बालकिशन, चौधरी रवीन्द्र सिंह, चौधरी जितेन्द्र बंसल, चौधरी धर्मेन्द्र सिंह, रूपराम माहौर, देवेन्द्र बाल्मीकि, प्रेमचंद प्रजापति, कालीचरन नेताजी, ब्रह्मपाल कश्यप, ठाकुर देवेन्द्र सिंह, सतीष चन्द शर्माजी, सुरेश दिवाकर, लवकुश, आर.ए. यादव आदि।

डॉ0 उदित राज ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह का हार्दिक स्वागत किया और इंडियन जस्टिस पार्टी के उन सभी नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ0 उदित राज ने उपस्थित

शेष पृष्ठ 4 पर...

डॉ. उदित राज पत्नी सीमा राज के साथ केक काटते हुए। साथ खड़े इन्द्रेश गजभिये व अन्य।

मंच पर बांये से डॉ. उदित राज, चौधरी रविन्द्र सिंह और जितेन्द्र बंसल एवं अन्य

डॉ. उदित राज के जन्मदिन के मौके पर उपस्थित अपार जनसमूह

जाति एवं भ्रष्टाचार

डॉ. उदित राज

गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक समाजशास्त्री आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य उत्सव में बयान दिया कि ''ज्यादातर भ्रष्टाचार में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होते हैं।'' इस बयान के कई पक्ष हैं। निर्विवाद रूप से यह इन वर्गों को कमतर रूप में दिखाता है और निंदनीय है लेकिन इसके और भी पक्ष हैं, यदि उन पर देश में बहस चलती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे को बल मिलेगा। इस देश में जाति से ज्यादा कोई और शाश्वत एवं ताकतवर चीज नहीं है। मरते दम तक इंसान जाति से मुक्त नहीं हो पाता। देश छोड़कर किसी भी मुल्क में चला जाए तो जातीय भावना भी साथ जाती है। इस बयान पर तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जाति नहीं होती तो कुछ ने कहा कि इस वाक्य को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। जो इन्होंने बोला वह वापिस तो नहीं हो सकता लेकिन अगर भ्रष्टाचार पर उसी तरह से बहस देश में छिड़ जाए जैसे निर्भया के हत्या एवं बलात्कार के ऊपर हुआ तो कुछ मकसद हासिल हो सकता है।

दलित–आदिवासी औरों की तुलना में तो कम से कम भ्रष्ट है और यह बहुत विश्वास के साथ कहा जा सकता है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने 17 लोगों के नंबर 2 विदेशी खाते का नाम सहित खुलासा किया उसमें से एक भी दलित और आदिवासी नहीं है। जैन हवाला कांड में भी ये नहीं थे। लाखों करोड़ों धन विदेश में है। बहुत संभव है कि उसमें ये ना शामिल हो। हर्षद मेहता, केतन पारिख, तेलगी आदि घोटालोंबाजों में से कोई दलित, आदिवासी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला था। कावेरी गैस के मामले में सरकार को 44,000 करोड़ का चुना लगा। कोल आवंटन का बंदरबांट सभी जानते हैं। जी–2 स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेने वाले में कोई भी इनमें से नहीं था। मंत्री जरूर दलित समाज का था। यह कहना गलत नहीं है कि दलित, आदिवासी अगर भ्रष्ट हैं तो अपवाद स्वरूप अर्थात दाल में नमक के बराबर। पिछड़े वर्ग के लोग कुछ अधिक हो सकते हैं लेकिन आबादी के अनुसार वह भी अपवाद ही होगा। आशीष नंदी ने जो कहा अगर उस बयान को उल्टा कर दिया जाए तो वह एक स्थापित सच्चाई होगी अर्थात् सवर्ण भ्रष्ट ज्यादा होते हैं।

जिस जाति के हाथ में हजारों वर्ष से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सत्ता रही है, वही तो और संस्थाओं को जन्म देता है। भ्रष्टाचार हमारे यहां एक संस्था का रूप ले चुका है। आजादी के बाद कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की बागडोर ज्यादातर सवर्णों के हाथ में ही रही है इसलिए यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद उसी समय में पड़ी। शासक वर्ग ही तमाम संस्थाओं, मान्यताओं एवं रीति–रिवाज का जन्मदाता होता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार धर्म के नाम पर होता है। देवी–देवताओं को प्रसाद, पैसा, चादर, सोना–चांदी, मुर्गा एवं बकरा आदि चढ़ाकर के लाभ लेना क्या भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ? निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की

शेष पृष्ठ 3 पर...

पूना पैक्ट
और उससे पहले

विशाल मंगलवादी

कई उच्च जातीय भारतीय यह मानते हैं कि भारत के दलितों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। तथ्य बताते हैं कि उत्पीड़ित वर्ग के साथ कांग्रेस ने 1917 के बाद से संपर्क साधना शुरू किया, और शुरू से ही कांग्रेस की नीयत शक के दायरे में रही। उस इतिहास की एक संक्षिप्त रूपरेखा काफी ज्ञानवर्धक है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 20 अगस्त, 1917 को भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टैग्यू ने ब्रितानी सरकार की ओर से एक औपचारिक घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि युद्ध उपरांत भारत के विषय में उनकी सरकार की मंशा यह है कि ''स्वायत्त संगठनों का विकास किया जाए ताकि भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के तौर पर, जिम्मेवार सरकार की क्रमिक स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो''। इस घोषणा का अर्थ यह लगाया गया है कि भारत को वैसी ही स्वायत्तता प्राप्त होगी जैसी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पहले से ही मिली हुई थी।

भारतीय राजनेता इसी प्रकार की उद्घोषणा की आशा कर रहे थे और भारत की संवैधानिक संरचना में बदलाव की योजनाएं बना रहे थे जो उनके हितों के अनुरूप हो। 1916–1918 के दौरान जिन दो योजनाओं ने खास ध्यान खींचा वे थीं, ''कांग्रेस–लीग योजना'' जो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित थी और दूसरी ''मॉन्टैग्यू–चेम्सफोर्ड योजना'' जो संसदीय प्रणाली के पक्ष में थी।

अपनी योजना को एकमात्र 'राष्ट्रीय मांग' के रूप में पेश करने के लिए कांग्रेस की निचली जातियों के समर्थन की आवश्यकता थी। उसके सामने समस्या यह थी कि हालांकि मुस्लिम लीग ने उसके प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था, ''डिप्रेस्ड क्लासिज'' कांग्रेस के उच्च जातीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं करती थीं। 1895 में, कांग्रेस के कुछ नेता सोशल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को यह अनुमति देने के लिए राजी हो गए थे कि उनके मंच से वे हिंदू सामाजिक व्यवस्था द्वारा भारतीयों को गुलाम बनाए जाने का विरोध कर सकें। यह विचार तब खारिज कर दिया गया जब श्री तिलक के अनुयायियों ने यह धमकी दी कि अगर उस मंच से किसी ने भी हिंदू प्रथाओं का विरोध करने की हिम्मत की तो कांग्रेस का पंडाल जला दिया जाएगा। इसके जवाब में 'अछूतों' ने कांग्रेस का विरोध किया और उसका पुतला जलाया। कांग्रेस के खिलाफ विरोध का यह तेवर 1917 तक बरकरार रहा जब कांग्रेस को उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ी।

इस अविश्वास के चलते कांग्रेस के लिए कांग्रेस–लीग योजना के लिए पिछड़े वर्गों का अनुमोदन प्राप्त करना टेढ़ी खीर बना गया। पूर्व में अपनी कायरता और उदासीनता के लिए क्षमा मांगने की बजाय कांग्रेस ने दलितों का समर्थन प्राप्त करने के लिए छल का सहारा लेने की कोशिश की। उन्होंने खुद एक प्रस्ताव लिखा और एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति– सर नारायण चंदावरकर, अध्यक्ष, डिस्प्रेस्ड, क्लासिज मिशन सोसाइटी– का इस्तेमाल करते हुए बंबई में 11 नवंबर 1917 को हुई एक बैठक में अन्य प्रस्तावों के साथ पास करवा लिया। प्रस्तावों के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

पहले प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई और साथ ही उस समय चल रहे पहले विश्व युद्ध में गठबंधन के लिए जीत की प्रार्थना की गई।

दूसरे प्रस्ताव में, जो बहुमत से पारित हुआ और जिसमें असहमति जताने वाले सदस्यों की संख्या कोई दर्जन भर थी, भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

तीसरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। ''... शोषित वर्गों की यह सार्वजनिक सभा यह महसूस करती है कि विधान परिषदों में सुधार और प्रनर्संगठन में सरकार को जो योजना भी पसंद आती है उसमें शोषित वर्गों के हितों का उचित ख्याल रखा जाए। इसलिए यह सभा अंग्रेज सरकार से निवेदन करती है कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए यह अधिकार दे कि वे परिषदों में अपनी संख्या के अनुपात से अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें।''

चौथा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। ''सरकार शिक्षा की अनिवार्य और निःशुल्क प्रणाली अपनाए।''

पांचवें प्रस्ताव के अनुसार, ''इस सार्वजनिक बैठक के अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निवेदन करे कि अपने आगामी सत्र में भारत के तमाम लोगों में एक अलग और स्वतंत्र प्रस्ताव की उद्घोषणा करे– धर्म और रीति रिवाजों द्वार शोषित वर्गों पर जो अक्षमताएं थोपी गई हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता, न्यायसंगतता और नैतिकता के विषय में। ... यह अक्षमताएं, जिनका उद्गम सामाजिक है, कानून और व्यवहार की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनैतिक मिशन और प्रचार का हिस्सा बनती है।''

छठा प्रस्ताव यह निवेदन करता है कि उच्च जातियों के सभी हिंदू, जो राजनैतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, शोषित वर्गों से अपमान के कलंक को दूर करने के लिए कदम उठाएं।

उपरोक्त बैठक के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद की एक बैठक की जिसमें शब्दाडंबर से भरपूर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :

''यह कांग्रेस भारत के लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे शोषित वर्गों पर रीति–रिवाजों द्वारा थोपी गई अक्षमताओं को दूर करने की आवश्यकता, न्यायसंगतता और नैतिकता पर गौर करें, यह अक्षमताएं बहुत ही पीड़ादायक और दमनकारी प्रवृत्ति की हैं और उन वर्गों के लिए अत्यंत कठिन और असुविधाजनक परिस्थितियां बनाती है।''

कुछ वर्षों बाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने उपरोक्त प्रस्ताव को एक ''विचित्र घटना'' (अ स्ट्रेंज इवेंट) बताया। कांग्रेस 32 वर्षों से सक्रिय थी, इस दौरान उसने भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता की बात उठाई, ब्रितानी राज के खिलाफ अभियान चलाया लेकिन उसने कभी भी निचली जातियों की आजादी की बात नहीं की। और अब जब उसे उनके राजनैतिक समर्थन की आवश्यकता थी, उसने अपने आप को उनके हक की बात करते हुए पाया– लेकिन सिर्फ उनका वोट लेने के लिए। श्री कांशीराम ने न्याय की ''छलपूर्ण'' अपील को ''शरारतपूर्ण'' करार दिया था ... बाद की घटनाओं ने साबित किया कि हिंदू समाज के उत्पीड़नकारी चरित्र को बदलने का कांग्रेस का कोई इरादा था ही नहीं। फिर भी, इस प्रस्ताव ने कांग्रेस को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि विदेशी शासन की अनैतिकता के अलावा भारतीय समाज के आंतरिक अत्याचार से निपटना भी जरूरी है।

बंबई में हुई पहली बैठक के कुछ दिनों बाद, उपरोक्त दर्जन भर विरोधियों ने निचली जातियों की एक अन्य बैठक का आयोजन किया, वह भी बंबई में। यही वह बैठक थी जिसने उच्च जातीय राजनेताओं के प्रति डॉ. अंबेडकर और श्री कांशीराम के रवैये को आकार दिया। एक गैर–ब्राह्मण पार्टी के नेता बापूजी नामदेव बगाडे ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने पिछली बैठक में पारित कुछ प्रस्तावों को खारिज कर दिया। दूसरी बैठक में पारित कुछ मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे :

1. ब्रितानी राज के प्रति निष्ठा

2. यह बैठक कांग्रेस–लीग योजना को समर्थन नहीं दे सकती, बेशक 11 नवंबर 1917 को हुई बैठक में इसे बहुमत प्राप्त हुआ था।

3. इस बैठक में यही समझ बनी है कि भारत का प्रशासन मुख्यतः अंग्रेजों के नियंत्रण में रहे जब तक कि सभी वर्ग और खासतौर पर शोषित वर्ग उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते जहां वे देश के प्रशासन में प्रभावकारी रूप से भाग ले सकें।

4. अगर अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता को राजनैतिक छूट देने का फैसला किया है तो यह बैठक सरकार से निवेदन करती है कि वह अछूतों को यह अधिकार दे कि वे विभिन्न वैधानिक निकायों में अपने प्रतिनिधि चुन सकें जिससे उनके नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सके।

5. यह बैठक बहिष्कृत भारत समाज के उद्देश्यों का अनुमोदन करती है और उसकी ओर से श्री मॉन्टेग्यू को भेजे जाने वाले शिष्टमंडल का समर्थन करता है।

6. यह बैठक सरकार से निवेदन करती है कि वह शोषित वर्ग की खास जरूरतों पर गौर करे, प्राथमिक शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य बनाए। यह बैठक सरकार से यह विनती भी करती है कि शोषित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों के रास्ते विशेष सुविधाएं भी प्रदान करें।

7. यह बैठक अध्यक्ष को यह अधिकार देती है कि वह उपरोक्त प्रस्तावों को वायसराय तथा बंबई सरकार तक पहुंचाए।

वस्तुतः इस बैठक ने यह घोषणा की कि बजाय इसके कि भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो और शासन ब्राह्मणों के हाथों में आ जाए, दलित अंग्रेजी राज के अधीन रहना ही पसंद करेंगे। जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने बाद में अपनी पुस्तक 'जातिभेद का उच्छेद' में कहा, ''जातिविहीन समाज की स्थापना किए बगैर स्वराज्य का कोई महत्व नहीं।'' यह इसलिए क्योंकि उन्हें अपने अनुभव से यह मालूम था कि ''सामाजिक क्रूरता के मुकाबले राजनैतिक क्रूरता कुछ भी नहीं है।''

निचली जातियों में व्याप्त इस मनोभाव ने महात्मा गांधी को उनकी ''मुक्ति'' के लिए प्रयास करने को विवश कर दिया।

डॉ. अंबेडकर ने इस दावे को हालांकि अपनी पुस्तक 'व्हॉट गांधी एंड द कांग्रेस हैव डन टू दि अनटचेबल्स' में खारिज किया है। उनकी दलील थी कि देश की आजादी के संघर्ष के दौरान भी महात्मा गांधी और कांग्रेस ने निचली जातियों को छलने का हर संभव प्रयास किया कि वे ऊंची जातियों के नियंत्रण में रहें। यहां उस दलील के विस्तार में जाना जरूरी नहीं है। उनकी दलील इस महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित थी :

लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में यह घोषणा करने के बाद कि अंग्रेजी सरकार 1917 में भारत को स्वराज्य देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी, लंदन में 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलनों का दौर चला ताकि सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तय की जा सके। अनुसूचित जातियों के नेताओं ने मांग की कि चूंकि ऊंची जातियां उनके विषय में गंभीर नहीं है, उन्हें अपने स्वंय के विधायक चुनने की अनुमति मिले, ताकि उनके प्रतिनिधि उनके नजरिए का प्रतिनिधित्व कर सकें।

महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसी कोई भी योजना उच्च और निम्न जातीय हिंदुओं में मौजूद दीवार को और मजबूत करेगी। उनका प्रस्ताव था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के द्वारा विधायकों को चुनें। इस प्रकार प्रत्याशी सारे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा न कि केवल अनुसूचित जातियों का।

हालांकि गांधी का प्रस्ताव सुनने में अच्छा लगता था लेकिन इसमें एक समस्या थी। इसका अर्थ हुआ कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन जिस उम्मीदवार को उच्च जातीय समर्थन प्राप्त होगा वह हमेशा जीतेगा। इसलिए किसी भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को जीतने के लिए उच्च जातीय मतदाताओं के अधीन होना पड़ेगा। गोलमेज सम्मेलनों में इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला, और गांधी समेत सभी प्रतिभागियों ने यह सहमति जताई कि अब मामला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ही सुलझाएंगे, और उनका फैसला हर किसी को मान्य होगा।

अंग्रेज सरकार ने 17 अगस्त, 1932 को डॉ. अंबेडकर के प्रस्ताव के पक्ष में अपने 'कम्यूनल अवार्ड' की घोषणा की। गांधी को डॉ. अंबेडकर की योजना में एक नया खतरा दिखने लगा। अगर डॉ. अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ने श्री जिन्नाह की मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया तो क्या होगा? एकसाथ, मुसलमानों और निचली जातियों को उच्चवर्णीय हिंदुओं को संख्या की लड़ाई में मात देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। प्रजातंत्र– संख्या का खेल– इस रूप में ऊंची जातियों के खिलाफ जाएगा।

इसलिए महात्मा गांधी ने पूना में अपना सबसे लंबा आमरण अनशन आरंभ कर दिया। यह अनशन औपनिवेशक राज के खिलाफ नहीं था। इसका उद्देश्य डॉ. अंबेडकर ने 19 सितंबर, 1932 के अपने इस वक्तव्य में बयान की :

''मैं सोचता था कि शोषित वर्गों का कोई भी शुभचिंतक उनके लिए नए संविधान के तहत अधिक से अधिक राजनैतिक ताकत हासिल करने के लिए जी–जान से संघर्ष करेगा ... कम्यूनल अवार्ड के अंतर्गत जो थोड़ी–बहुत राजनैतिक ताकत शोषित वर्ग को प्राप्त हुई है (गांधी) न केवल उसे बढ़ाने का कोई यत्न नहीं कर रहे बल्कि जो मामूली ताकत उन्हें हासिल है उसे भी छीनने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं।''

डॉ. अंबेडकर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया कि वह मुक्ति की इस संभावना का समर्पण कर दें और गांधी की जान बचाएं। महात्मा गांधी के उच्च जातीय अनुयायियों ने धमकी दी कि अगर गांधी की मृत्यु हो गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। डॉ. अंबेडकर का बयान इसकी पुष्टि करता है :

''चाहे वह जानते हैं या नहीं, महात्मा के इस कदम का परिणाम देशभर के शोषित वर्गों के खिलाफ उनके अनुयायियों के आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं होगा। ... महात्मा जी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश ताकतों को खुला छोड़ रहे हैं, और इस तरह के तौर–तरीके अपना कर हिंदू समुदाय तथा शोषित वर्गों के बीच नफरत की भावना के बीज बो रहे हैं, इससे दोनों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है।''

डॉ. अंबेडकर को एहसास था कि अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो बड़ी संख्या में अछूतों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए गांधी और साथी अछूतों की जान बचाने के लिए उन्होंने 24 सितंबर, 1932 के पूना पैक्ट के द्वारा उनकी राजनैतिक ताकत का परित्याग कर दिया। इसके नतीजतन, आजादी के 50 सालों में ज्यादातर समय निचली जातियों को उच्च जातीय शासकों के अधीन ही रहना पड़ा है। राजनैतिक रूप से तो गांधी सफल हो गए, लेकिन इससे उन्होंने केवल यही सुनिश्चित किया की आजाद भारत में भी निचली जातियां उच्च जातियों के गुलाम ही रहे। डॉ. अंबेडकर के अनुसार जिस संयुक्त निर्वाचन की नीति को लागू करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दांव पर लगा दी वह हिंदुओं के नजरिए से रॉटन बरो (इंग्लैंड का ऐसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां निर्वाचकों की आबादी कम हो चुकी है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व पहले के समान कायम हो) की नीति थी जिससे हिंदुओं को यह अधिकार मिल गया कि वह एक अछूत को नामांकित कर सकें जो केवल नाम के लिए अछूतों का प्रतिनिधि होगा लेकिन वास्तविकता में हिंदुओं का औजार बन कर रहेगा।

पिछड़ों के लिए अलग नजरिया क्यों?

डॉ. उदित राज

जब कोई काम दलित–पिछड़ा करे तो नीच, हेय एवं घृणित दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा मापदंड सवर्णों ने ही बनाए। जो मान्यता, धंधा, काम इनके हित साधे वह श्रेष्ठ और सम्मानजनक माना जाए और जो इनके वश, सीमा और क्षमता से बाहर हो वह धर्म, समाज विरोधी व नीच माना जाता है। सदियों से लेकर आज तक यही सोच बनी हुई है। पहले नृत्य, संगीत, गायन, नाटक, चित्रकला आदि पर वर्चस्व दलितों और पिछड़ों का हुआ करता था तो इसे घृणा के दृष्टि से देखा जाता था। सवर्ण इनको नचनिया, गवैया, भांड, ढ़ोलबाज, नट आदि तिरस्कृत उपमाओं से अपमानित करते थे। इन कलाओं को देखना हिंदू धर्म के खिलाफ माना जाता था। कलाकारों को भिखारियों का दर्जा दिया गया लेकिन शहरी सभ्यता विकसित होने के कारण इनका सवर्णीकरण हुआ। यहां तक कि सवर्णों ने इसे अपनी मौलिक कला बताकर पूरे विश्व में वाहवाही लूटी। अब इन कलाओं को सीखाने के लिए बड़े–बड़े शहरों में संस्थान, सांस्कृतिक केंद्र, कला मंडल और अकादमी स्थापित हो गए हैं और जिन पर सवर्णों का कब्जा हो गया है। शूद्र देवदासियों को आज भी नफरत से देखा जाता है लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं ने नृत्य और संगीत को बचाया। समय ने करवट ली और फिल्मों के जरिए ये कलाएं लोकप्रिय हो गई। राजस्थान में सपेरा कालबेलिया नर्तकी गुलाबो ने पूरे विश्व में नाम कमाया लेकिन अब उस कला पर सवर्ण स्त्रियों ने कब्जा जमा लिया और यह कला सम्मानजनक हो गई। एक समय में दलित–आदिवासी गांव के खुली चौपाल में नाचा–गाया करते थे उस समय उन्हें भांड–नचनिया, बहुरूपिया कहा जाता था लेकिन आज उसी कला पर टीवी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निम्बूडा–निम्बूडा लोकगीत बाड़मेर, राजस्थान के पिछड़े लोक कलाकार वर्षों से गाते रहे लेकिन किसी ने नहीं पूछा और जब इसी को ऐश्वर्या ने फिल्म में गाया तो लोकप्रियता बढ़ गई।

आजादी के बाद लगभग तीन दशक तक दलित एवं पिछड़ों की भागीदारी राजनीति में नहीं के बराबर रही। यदि आरक्षण की वजह से लोग चूनकर के आए भी तो उनमें से ज्यादातर गुंगे–बहरे की भूमिका निभाते रहे तो राजनीति सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता था। स्कूल में अध्यापक बच्चों से कहते थे कि बड़ा होकर के क्या बनोगे तो उन्हें सिखाते थे कि कहो नेहरू चाचा बनेंगे। समय के अनुसार परिस्थिति बदली है और ज्यादातर प्रांतों में सत्ता पिछड़ों के हाथ में आयी तो राजनीति को ही गंदा कह दिया गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वजह से दलितों एवं पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी है तो कामकाज ही भ्रष्ट ही निकम्मा दिखने लगा है। हर तरफ से आवाज उठती है कि सरकारी विभाग भ्रष्ट और निकम्मे हो गए हैं और निजीकरण ही एक उपाय है। निजीकरण होने से सवर्णों का दबदबा फिर से हो जाएगा। शिक्षा का निजीकरण हुआ जिसमें आधिपत्य सवर्णों का है। आज यह क्षेत्र लाभ कमाने में सबसे आगे हो गया है लेकिन क्यों नहीं इसे बदनाम किया जाता। आजादी के पहले जब सवर्ण ही सरकारी नौकरियों में आधिपत्य जमाये तो उन्हें गद्दार क्यों नहीं कहा गया।

आजादी के बाद देश का शासन–प्रशासन सवर्णों के ही हाथ रहा है तो इस तरह से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुनियाद की नींव उन्होंने ही डाली। भ्रष्टाचार कुछ महीनों में ही जन्म नहीं लेता है, जड़ जमाने में कई दशक लगता है। निःसंदेह आज आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है लेकिन इसके लिए वर्तमान के राजनैतिक एवं नौकरशाह उतना जिम्मेदार नहीं हैं जितना की शुरुआती दौर वाले। जैसी बुनियाद होती है वैसे ही घर की दीवारें और छत तैयार होती है और यह समझना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आशीष नंदी का ही बयान अगर लें ले तो भी यही बात सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि अब दलित, पिछड़े और आदिवासी ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं। उनका यह कथन सच तो नहीं है इसलिए कि भ्रष्टाचार की बुनियाद इन्होंने नहीं डाला और सवर्णों के मुकाबले में आज भी ये भ्रष्टाचार में बहुत पीछे हैं। पिछले वर्ष 17 भारतीयों के नंबर 2 के खाते विदेश में मिले और सरकार ने खुलासा किया लेकिन उसमें से एक भी दलित, आदिवासी नहीं हैं। लाखों करोड़ काला धन बाहर जमा हुआ है और यह कहा जा सकता है कि दलित, आदिवासी तो उसमें शामिल ही नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ पिछड़ें हों लेकिन जितनी बड़ी उनकी आबादी है उसके अनुपात में नगण्य ही होगा। यह भी देन उसी भ्रष्टाचार संस्कृति की है जिन्होंने इसको पनपाया। आशीष नंदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के तरीके अलग–अलग हैं। सिफारिश से यह कोई व्यक्ति अपने औलाद का दाखिला हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में करा देता है तो उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाता जबकि यह है। प्रख्यात पत्रकार आशुतोष ने उसी समय कहा कि सवर्णों के भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आते क्यूंकि उन्हें तमाम तरीके मालूम हैं। जेएमएम घूस कांड में जो दलित, आदिवासी समाज के सांसद थे उन्हें भ्रष्टाचार करना नहीं आता था और जो नगद पैसा मिला सीधे उन्होंने बैंक में जमा कर दिया और पकड़ लिए गए। चालाक लोग हजारों करोड़ रिश्वत लेकर भी पकड़ में नहीं आते। कावेरी गैस में 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स या कोल आवंटन का घोटाला हो इसमें दलित, आदिवासी तो नहीं शामिल हैं फिर भी इन्हीं को ज्यादा भ्रष्ट कहा जा रहा है। इस बयान को एक अवसर के रूप में भी लिया जा सकता है कि जैसे निर्भया के बलात्कार और हत्या पर देश में बहस चली उसी तरह से अब बहस चले कि कौन सी जाति ज्यादा भ्रष्ट है तो असलियत सामने आ जाएगी। जब थाने की दलाली निम्न वर्ग के लोग करते हैं तो एक बड़ी चर्चा हो जाती है कि ये लोग दलाल और भ्रष्ट हैं और जब वही काम सवर्ण करें तो माना जाता है कि उनकी पहुंच लंबी है और उसी की वजह से राहत मिली। भ्रष्टाचार के अलग–अलग ये पैमाने क्यों है उसको समझने के लिए समाज की मानसिकता को जानना होगा।

जिन क्षेत्रों में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े नहीं हैं उन्हें अभी भी पवित्र गाय माना जाता है। सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार इस समय कहीं है तो कॉरपोरेट हाउसेज में लेकिन वह लोगों के नजरों में नहीं आता क्यूंकि उसमें निम्न जातियों की भागीदारी नहीं है। उच्च न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को कौन नहीं जानता लेकिन बहुत ही कम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जिस दिन दलितों, आदिवासियों की भागीदारी होगी तो जिस तरह से नौकरशाही और राजनीति बदनाम हुई है वही हश्र इसका होगा। अब सेना में भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। मीडिया अभी भी पवित्र गाय मानी जाती है लेकिन वहां का भ्रष्टाचार लोगों को नहीं दिखता और ऐसा इसलिए है कि दलित एवं आदिवासी की भागीदारी शून्य है। मैं दो बार चुनाव लड़ा हूं और ज्यादातर अखबार एवं चैनल के पत्रकारों ने सीधे पैसा मांगा और ना देने पर यह भी कह दिया कि या तो खबर नहीं छापी जाएगी या विरोध में बात लिखी जाएगी। हालत यहां तक पहुंच गई है कि विज्ञापन पैकेज के नाम पर लाखों का हिसाब–किताब होता है और गरीब प्रत्याशी बेचारा असहाय बनकर के ताकता रह जाता। मीडिया का भ्रष्टाचार दिखता नहीं लेकिन औरों के अनुपात में यहां ज्यादा ही है। जिस दिन धार्मिक प्रतिष्ठानों में इनकी भागीदारी हो गई तो उस दिन वहां भी भ्रष्टाचार दिखने लगेगा, जहां की आस्था के नाम पर सब कुछ हो रहा है।

शेष पृष्ठ । का...

जाति एवं भ्रष्टाचार

बुनियाद रखने का काम सवर्णों ने किया और कुछ एक दशक से दलित, आदिवासी और पिछड़े भी इस सामाजिक बुराई से प्रभावित हुए हैं। असली गुनहगार वही जाति है जिसने इस सामाजिक बुराई को जन्म दिया है। अतः आशीष नंदी अपने में फिर से टटोलें कि जो उन्होंने कहा उसका विपरीत जरूर सच है। हमारे यहां के ज्यादातर बुद्धिजीवी बौद्धिक स्तर पर ईमानदार नहीं है और दूसरी तरफ समाज के सच्चाई का ज्ञान भी नहीं है। किताबी कीड़ा हो जाने से कोई बुद्धिजीवी नहीं हो जाता। यूरोप और अमेरिका से विपरीत हमारे यहां जब समाज में बदलाव आ जाता है तब बुद्धिजीवी संज्ञान लेते हैं उनमें कम ही क्षमता है कि वे अपनी लेखनी, वक्तव्य, कविता आदि से समाज को प्रभावित किए हैं। आखिर में आशीष नंदी इसी माहौल के पैदाईश हैं और उनसे कोई बड़ी उम्मीद तो की नहीं जा सकती।

आशीष नंदी ने यह भी कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार कम है उसका श्रेय उन्होंने वामपंथी सवर्ण नेताओं को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 100 वर्ष में कोई दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा नेतृत्व में नहीं है। अर्थात् आर्थिक भ्रष्टाचार कम हुआ लेकिन सामाजिक पलड़ा ज्यादा ही भारी है। दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के लिए अच्छा होता कि वहां भी उतना ही आर्थिक भ्रष्टाचार होता जितना और स्थानों पर है बशर्ते वे इस शर्त पर शासन–प्रशासन में भागीदार होते। ऐसा इसलिए कि इस माहौल में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होती। इस देश में भागीदारी की समस्या कहीं आर्थिक भ्रष्टाचार से बड़ी है। वामपंथी भले इसको ना माने लेकिन यह एक कटू सत्य है। वामपंथियों द्वारा इस सच्चाई से रूबरू ना होने के कारण उनका सफाया हुआ नहीं तो भारत देश जैसे उर्वरा भूमि रूस की भी नहीं थी जहां पर मार्क्सवाद पनपा। अभी तक जो आरोप वामपंथियों पर लगाया जाता रहा कि वे सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं, वह सच है। आशीष नंदी के बयान से इस सोच को समर्थन मिला। यह कैसे संभव है कि लगभग 80 प्रतिशत दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों की आबादी हो और उसमें से नेतृत्व ना पैदा हो। क्या मान लिया जाए कि ये मूर्ख एवं अयोग्य होते हैं।

जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के संघर्ष पर देश में बहस छिड़ी उसी तरह से इस विषय पर देश में संवाद होना चाहिए कि कौन जाति ज्यादा भ्रष्ट है और कौन नहीं। बहस से स्पर्धा होगी और जो जातियां ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक और मानसिक दबाव पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। हमारे यहां शान एवं स्पर्धा से चीजें तेजी से भागती है। जिस जाति के शान पर बट्टा लगेगा वह भ्रष्टाचार से बचेगी। कुछ दिन पहले इसी मुद्दे पर एन डी तिवारी हॉल, नई दिल्ली में विचार गोष्ठी रखी गई थी। वहां पर अन्ना हजारे से मुलाकात हो गई और मैंने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उनके अनशन से क्या फायदा हुआ। उन्होंने जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भारत के गांव में जाना होगा। मैंने कहा कि 6 लाख से ज्यादा गांव भारत में है तो कैसे ये संभव होगा और कितने हजार साल लगेंगे क्यूंकि उन्होंने पूरा जीवन एक गांव को सुधारने में लगा दिया। ज्यादातर लोग नकार रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जाति नहीं होती लेकिन यह सच नहीं है। जाति अथवा हमारी सामाजिक संरचना ही झूठ पर आधारित है। ऊंच–नीच भगवान की मर्जी है, इसी मान्यता पर समाज टिका हुआ है तो क्या यह सत्य है। असत्य बात अपने आप में भ्रष्टाचार है। आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि बौद्धिक भ्रष्टाचार को मान्यता ना मिले और उसको मिटाने के लिए लगातार संघर्ष हो। यह बात तो तय है कि यदि जाति और भ्रष्टाचार में बहस चले तो इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

दलित, आदिवासी एवं पिछड़े छात्रों का संगठन जरूरी

हर्षवर्धन दवणे

हजारों वर्षों से सवर्ण समाज ने दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों को शिक्षा, भागीदारी एवं सम्मान से वंचित रखा। गुरू और शिष्य की परंपरा रही, जिसमें दलित, पिछड़े एवं आदिवासी शामिल ही नहीं थे। धोखे से यदि इस वर्ग के लोगों ने ज्ञान और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश भी की तो अंगूठा एवं सिर काट लिया गया। उस सवर्ण संस्कृति के भगवान ने भी दलित की पूजा करने पर गर्दन काटी है। अंग्रेज न आते तो शायद अब तक शिक्षा का द्वार हमारे लिए बंद रहता। ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष ने न केवल दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों की शिक्षा के लिए प्रयास किया बल्कि स्त्रियों के लिए भी। डॉ0 अम्बेडकर ने सबसे अधिक शिक्षा को महत्त्व दिया और आवाहन किया कि 'शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो।' शिक्षा के बिना इंसान पशु समान है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सदियों तक हमें पशु बनाकर रखा गया। अब हमें यह मंजूर नहीं और ज्ञान प्राप्ति हमारी प्राथमिकता है। हम तो कहते हैं कि चाहे खाना पूरा न मिले तो भी स्वीकार है, लेकिन ज्ञान के बिना जिंदगी जीना मौत के समान है।

विशेष रूप से दलित–आदिवासी समाज के छात्र एवं युवा निजीकरण एवं उदारीकरण के शिकार इतने हद तक हो गए हैं कि उनमें से ज्यादातर अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर भी नाकाम हो रहे हैं। इस समाज में शिक्षा इसलिए भी आयी कि आरक्षण की वजह से पहले सरकारी नौकरी लग जाती थी। सन् 2000 में अनुसूचित जाति/जन जाति की संख्या सरकारी नौकरियों में लगभग 40 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब अनुमान के अनुसार लगभग 27 लाख ही रह गयी है और आगे कम होती ही जाएंगी। निजी क्षेत्र में नौकरियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, उसमें हमें रोजगार मिलना नहीं है चाहे जितने पढ़े–लिखे हों, क्योंकि उद्योग एवं व्यापार ज्यादातर सवर्णों के ही हाथ में है। डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ गत् 10 वर्ष से निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस वर्ग के छात्र एवं युवा साथ में संघर्ष करने की बात तो दूर, उन्हें जानकारी ही नहीं है। निजीकरण की मार हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। अब सरकारी स्कूलों एवं संस्थाओं में ज्यादातर पढ़ने वाले दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के ही छात्र हैं, क्योंकि सवर्णों ने अपने लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थाएं बना लिए हैं। धन की ताक़त की वजह से उनके बच्चे विदेशों में भी पढ़ रहे हैं। इस तरह से दोहरी मार हमारे ऊपर पड़ रही है।

परिसंघ के आंदोलन के कारण केन्द्र सरकार ने 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया था कि निजीक्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों की एक कमेटी भी बनी और उसने निजी क्षेत्र मे आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की। 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय में इसके लिए कोर्डिनेशन कमेटी बनी और वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारियों की एक कमेटी 2008 में बनी, फिर भी अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। देश के पूंजीपति संगठन जैसे – सी.आई.आई., फिक्की, एसोचेम आदि ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध किया, यह कहते हुए कि वे स्वतः हमारा उत्थान करेगें लेकिन वह सब बेईमानी साबित हुई। यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलता है तो उसका लाभ हम छात्रों एवं युवाओं को मिलेगा न कि परिसंघ के कर्मचारियों–अधिकारियों को। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि निजीक्षेत्र में आरक्षण नहीं तो पढ़ाई–लिखाई का मतलब नहीं। महाराष्ट्र को छोड़कर देश के किसी और राज्य में छात्र एवं नौजवान इन मांगों को लेकर संघर्ष करने की बात तो दूर की है, वे जानते ही नहीं। छात्रावास जो पहले बने थे, उनका भी रखरखाव नहीं हो पा रहा है, नए तो बन ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई एवं फीस में जो वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में स्कालरशिप नहीं बढ़ी और जो लागू है, वह भी नहीं मिल पाती। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण न होने की वजह से हम वहां पढ़ नहीं पाते। पढ़ना भी होता है तो मां–बाप कर्ज में डूबकर फीस आदि का भुगतान कर पाते हैं। जहां निजी क्षेत्र में पढ़ने का मौका मिला भी है, वहां पर सरकार की स्कालरशिप नाम–मात्र की है और 70 प्रतिशत से अधिक का भुगतान स्वयं करना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई हो ही नहीं सकती।

हमने दलित–आदिवासी छात्र एवं युवा की बात पहले की लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। अपवाद को छोड़कर पिछड़े वर्ग में सामाजिक एवं शैक्षणिक अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होता है। जब 2006 में पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो उसका विरोध सवर्ण समाज की ओर से हुआ। दलित समाज आगे आकर जवाब दिया न कि पिछड़ा वर्ग। डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में देश में जगह–जगह पर इनका मुकाबला हुआ और दिल्ली स्थित एम्स जो आरक्षण के विरोध का केन्द्र बन गया था, उसका घेराव किया गया और उससे आरक्षण विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई भी अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों ने लड़ी थी। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें वी.पी. सिंह जी की सरकार ने लागू किया तो ज्यादातर विरोध करने वाले पिछड़े वर्ग के ही लोग थे और जिस प्रथम छात्र ने इसके विरोध में आत्मदाह किया था वह पिछड़े वर्ग का ही था। यह सच्चाई है कि पिछड़े वर्ग में अम्बेडकर, फुले, शाहू आदि के विचारों का फैलाव नहीं हुआ इसलिए उनमें अधिकार को पाने के लिए चेतना नहीं पैदा हो पाई। हम इनका भी पूरा साथ चाहते हैं, लेकिन यदि भागीदारी नाममात्र की होगी तो बात नहीं बनेगी। पिछड़ों की आबादी 52 प्रतिशत है, 10 प्रतिशत् भी पिछड़े हमारा साथ दे दें तो भी हमें खुशी होगी। इनकी उदासीनता का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि सन् 2002 से 27 प्रतिशत आरक्षण मिला है, लेकिन अभी तक 6 प्रतिशत तक भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। इनकी ज्यादातर वैचारिक एवं अधिकारों की लड़ाई दलित ही लड़ते हैं।

हम राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रबल पक्षधर हैं, यह न केवल शब्दों में बल्कि व्यावहारिकता में होना चाहिए। दूसरे छात्र संगठन राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात तो करेगें लेकिन समाज एवं सरकार में भागीदारी के बिना। हमारा देश 2000 वर्ष तक गुलाम इसलिए था कि सभी वर्गों एवं जातियों की भागीदारी नहीं थी और प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी ही भारत को महाशक्ति बना सकता है। हम निजी क्षेत्र, पत्रकारिता, सेना, उच्च न्यायपालिका, फिल्म, पुरस्कार, खेल आदि सभी में आबादी के अनुपात में भागीदारी चाहते हैं। इससे न केवल दलित और पिछड़े सशक्त होगें बल्कि पूरे देश में सुख एवं शांति स्थापित होगी।

मनुवादी मीडिया हमारी बात को नहीं छापती है। विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति की वजह से अब सस्ती मीडिया जैसे – इंटरनेट, फेसबुक, ट्वीटर, ब्लाग, एस.एम.एस., मोबाइल फोन, मिस काल आदि उपलब्ध हो गए हैं। इसका इस्तेमाल करके अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। निर्भया का दिल्ली में बलात्कार एवं हत्या पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ तो इसी सोसल मीडिया के कारण। सवर्ण छात्रों एवं युवाओं से दस गुना सजगता से इस मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और हमारा प्रयास है कि सन् 2013 में एक लाख छात्र व नौजवान सोसल मीडिया के माध्यम से जुड़ें। यदि हम यह भी नहीं कर सकते हैं तो भूल जाएं कि हम भागीदारी की लड़ाई लड़ सकेगें। अन्ना हजारे जैसे लोगों ने कुछ दिनों में ही लाखों लोगों को सोसल मीडिया से जोड़ा तो क्या एक साल में हम उनसे ज्यादा नहीं जोड़ सकते।

संपर्कः 07709975562

शेष पृष्ठ । का...

भव्य रूप से मनाया गया डॉ. उदित राज का जन्मदिन

जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि आज उपस्थित लोग यह प्रतिज्ञा करें कि वे जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि को मिटाने वाली शक्तियों का समर्थन करेंगें। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग सफलता प्राप्त लोगों की ओर देखते हैं और उनसे मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके अंदर भी वह ऊर्जा और सामर्थ्य है, जिससे आप भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते उससे पहचानने और अमल में लाने की आवश्यकता है।

म0प्र0 सरकार में मंत्री एवं डॉ0 अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि कार्यक्रम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री इन्द्रेश गजभिये ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री पद तो तवायफ के पैरों में पाजेब की तरह होती है, जो कभी बांध दी जाती है तो कभी खोल दी जाती है, लेकिन डॉ0 उदित राज सहित आप सभी जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं वह हमेशा याद किया जाता रहेगा। अपने जीवन काल में एक उद्योगपति कितना भी धन अर्जित कर लें लेकिन मरने पर उसे कंधा देने के लिए कभी–कभी उसके परिवार तक के लोग मौजूद नहीं होते और यह कार्य उसके कर्मचारी करते हैं लेकिन जो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनके साथ पूरा समाज होता है।

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी, श्री सुरेश दीवान ने मंच का संचालन किया और समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तभी से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज का जन्मदिवस मनाते आ रहे हैं। हम इस समारोह को 'जस्टिस डे' के रूप में मनाते हैं। आज का यह समारोह चौधरी रवीन्द्र सिंह के विधान सभा क्षेत्र में मनाया जा रहा है, हम विश्वास दिलाते हैं कि यहां से चौधरी रवीन्द्र सिंह इंडियन जस्टिस पार्टी के टिकट पर चुनाव अवश्य जीतेगें।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, श्री परमेन्द्र एवं पार्टी की युवा इकाई के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर श्री संजय राज ने भी डॉ0 उदित राज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी।

चौ0 रवीन्द्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, इंजपा, ने समारोह में डॉ0 उदित राज एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से वायदा किया कि वे पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहेगें और सभी का सहयोग लेते हुए आगामी विधान सभा का चुनाव जीतने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगें। उन्होंने सभी अतिथियों को अपनी विधान सभा में हुए समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया।

मास्टर इन्द्रजीत, प्रदेश महासचिव, ने कहा कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना एवं समान व अनिवार्य शिक्षा है। सरकार ने शिक्षा का कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन दलितों व गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जबकि पब्लिक स्कूल जो इनसे कम संसाधनों में चल रहे हैं, वे बेहतर शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं। दलितों व गरीबों के बस की बात नहीं है कि वे निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकें। हमारा मानना है कि जब तक सभी को समान शिक्षा मुहैया नहीं करायी जाती तब तक दलितों व गरीबों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया जाता रहेगा। हम इस समारोह को 'जस्टिस डे' के रूप में मनाते हैं, जो न्याय का प्रतीक है और आज हम संकल्प लेते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना व समान व अनिवार्य शिक्षा के लिए जीवनपर्यंत संघर्ष करते रहेगें।

श्री जितेन्द्र बंसल, जिलाध्यक्ष – उत्तरी–पूर्वी दिल्ली, इंजपा, ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 उदित राज को आश्वासन दिया कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतने हेतु वे अभी से लोगों के घर–घर तक जाएंगें और बूथ स्तर तक की इकाइयों का गठन शीघ्र ही करेगें।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद कुमार ने भी माननीय उदित राज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी व समारोह को संबोधित किया।

समारोह में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज ने मुस्तफाबाद विधान सभा से चौधरी रवीन्द्र सिंह एवं करावल नगर विधान सभा से जितेन्द्र बंसल को आगामी विधान सभा चुनाओं हेतु इंडियन जस्टिस पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि चौधरी रवीन्द्र सिंह ने उ0प्र0 पुलिस में भर्ती होकर अपने कैरियर की शुरुआत की लेकिन पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार व गरीबों व दलितों के प्रति पुलिस उत्पीड़न इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने शीघ्र ही पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आर.एस.एस. से जुड़े किन्तु उसकी साम्प्रदायिक कटुता की वजह से दो साल में ही उसे भी त्याग दिया। वर्तमान में गुर्जर समाज सुधार समिति एवं डी.एल. एफ. सुधार समिति द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनकी इसी समाज के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए इन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस जन्मदिवस समारोह को देखते हुए लगता है कि मुस्तफाबाद से पार्टी के लिए इनके अलावा कोई अन्य उपयुक्त प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। डॉ0 उदित राज ने बताया कि श्री जितेन्द्र बंसल (एम.ए.बीएड) को 4 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में कार्य का अनुभव है। वहां से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज सेवा करने के लिए जुड़े लेकिन सुश्री मायावती जी की तानाशाही की वजह से एक वर्ष में ही पार्टी छोड़ दिया और वर्तमान में शिक्षा सुधार समिति में कार्यरत् हैं। पार्टी के मिशन सबको शिक्षा एवं सबको न्याय की बात इन तक पहुंचाने का श्रेय मास्टर इन्द्रजीत जी को जाता है और इसी भावना से प्रभावित होकर पहले इन्हें उत्तरी–पूर्वी दिल्ली का जिलाध्यक्ष बनाया गया था और आज इन्हें इंडियन जस्टिस पार्टी की ओर से करावल नगर विधान सभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है।

डिक्की और प्रकाश अम्बेडकर दलित विरोधी

स्वतंत्र मिश्र

हाल ही में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कामर्श एंड इंडस्ट्री (डिक्की) की उत्तर प्रदेश शाखा की लखनऊ में शुरुआत हुई। डिक्की के संरक्षक और दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि हम कास्ट (जाति) को कैपिटल (पूंजी) से शिकस्त देना चाहते हैं। चंद्रभान प्रसाद से जब इस वक्तव्य के बारे में पूछा कि क्या केवल कुछ लोगों की आर्थिक तरक्की हो जाने भर से जाति की समस्या खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक दलितों की मांगने वाले की छवि थी, पर वे अब देने के स्थिति में आ गए हैं। सच तो यह है कि डिक्की में 3,000 दलित बतौर उद्योगपति सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 करोड़ से भी ज्यादा है। दलित आबादी के बीच इन दलित उद्योगपतियों का प्रतिशत 0.0012 फीसदी के आसपास बैठता है। वैसे इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित चिंतक उदित राज डिक्की के इस पहल को दलित समुदाय के विकास की राह का रोड़ा ही मानते हैं।

डिक्की 2005 में बना। उत्तर प्रदेश की इकाई के बनते ही डिक्की की इकाइयों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। डिक्की की पंजाब इकाई भी जल्द ही शुरू होने जा रही है। इससे पहले संगठन की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि इकाइयां शुरू की जा चुकी हैं। डिक्की के संस्थापक और अध्यक्ष मिलिंद कांबले का मानना है कि दलितों में राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक नेतृत्व तो पहले से ही मौजूद है लेकिन उनके बीच व्यापारिक नेतृत्व की कमी थी, जिसे पूरा करने का काम डिक्की कर रहा है। यह पूछने पर कि डिक्की दलित समाज के आर्थिक बेहतरी के लिए क्या कर रहा है, मिलिंद कांबले ने बड़ी साफगोई से कहा कि हमने पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस मसले पर चंद्रभान प्रसाद की राय भी कुछ ऐसी ही है। वे भी कहते हैं कि देश के सभी सवर्ण जिस तरह उद्योगपति या करोड़पति नहीं हो सके, उसी तरह सारे दलित भी उद्योगपति या करोड़पति नहीं हो सकते हैं।

सच तो यह है कि आज भी दलित समाज का बहुत बड़ा हिस्सा मुफलिसी में जीने को मजबूर है। हर रोज देश के कोने–कोने से उनके उत्पीड़न और दमन की खबरें आती हैं। कुछ महीने पूर्व कर्नाटक राज्य में दलित जाति से संबद्ध रखने वाले एक आइएएस अधिकारी का स्थानांतरण हुआ, तब अगड़ी जाति के कर्मचारियों ने पूरे कार्यालय के प्रांगण को गोबर से लीपकर शुद्ध किया था।

उत्तर प्रदेश में डिक्की की इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल ज्यादातर कारोबारियों ने दलितों के आरक्षण का विरोध किया था। अध्यक्ष मिलिंद कांबले ने भी इस मौके पर कहा था, 'हम भी बाबा साहब आंबेडकर की तरह सूट पहनते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं। हम आरक्षण के बल पर नहीं, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं।'

कांबले सहित तमाम दलित उद्योगपतियों द्वारा आरक्षण का विरोध करना उनके आत्मविश्वास का परिचायक है, लेकिन यहां देखने लायक बात यह है कि आरक्षण का विरोध करने वाले ये वे लोग हैं, जिनकी कंपनी का टर्नओवर 25–50 करोड़ रुपये सालाना है।

दलित चिंतक उदित राज का इन दलित उद्योगपतियों के विपरीत यह मानना है कि दलित समाज को मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए अभी भी कम–से–कम 50–100 वर्ष आरक्षण की जरूरत है। वे डिक्की के सदस्यों द्वारा आरक्षण का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर तल्खी से भरकर कहते हैं, 'डिक्की से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनके सदस्यों द्वारा आरक्षण का विरोध किए जाने की बात नहीं पचती है। वे मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। सारे दलित कारोबारियों की कुल संपत्ति कुछ मझोले कद के सवर्ण उद्योगपतियों के पूंजी के बराबर भी नहीं होगी। बड़े शहर की किसी एक अमीरों की कॉलोनी में जितने सवर्ण पूंजीपति रहते हैं, उतने पूरे देश में दलित एवं आदिवासी व्यापारी नहीं होगे। सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में काम पहले से भी किया गया है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अभी शुरू होना है। अनुसूचित जाति/जन जाति परिसंघ की ओर से कन्फेडरेशन ऑफ दलित इंटरप्रेनियर की शुरुआत की जा रही है और अभी से खोज छोटे एवं मझोले व्यापारियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अपवाद से समाज चलता नहीं है। देश में दो चार मध्यम या बड़े स्तर के पूंजीपति इस समाज से होगें वरना अभी तक ये लघु एवं छोटे व्यापार के स्तर तक ही पहुंच पाएं हैं। मध्यम स्तर के व्यापारी (मीडिया मस्केल इंडस्ट्री) भी बिरले देखने को मिलते हैं। ऐसे में आरक्षण का विरोध करके या आरक्षण हमें नहीं चाहिए लोग या संगठन जितने घातक सिद्ध होगें उतना सवर्ण भी नहीं। आरक्षण हमारा जीवन है। बिना आरक्षण के अभी भी हम 50–100 साल तक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं, उल्टे निजीकरण की वजह से और पिछड़ गए हैं। निजीकरण की वजह से जो नए क्षेत्र पनपे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था में निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं, वे हैं – आई. टी., टेलीकॉम, कांस्ट्रक्शन, एफ. डी.आई., निजी शिक्षा, मीडिया, शेयर बाजार आदि। इसमें दलितों–आदिवासियों की आबादी लगभग शून्य के बराबर है। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर ने आरक्षण को खत्म करने की बात हाल में कही है, जो बहुत ही दुखद है। इसके पीछे सवर्णों की साजिश भी लगती है कि इन लोगों को अपना कहीं एजेंट तो नहीं बना लिया है। एक मूर्ख आदमी भी आराम से कह सकता है कि आरक्षण अगर न होता तो दलित–आदिवासी कहां होते?आसानी से कहा जा सकता है कि अभी भी ये गुलाम होते क्योंकि जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, वहां भागीदारी शून्य है।''

डिक्की में शामिल उद्योगपतियों के शेयर नैनो, पल्सर और हीरो मोटर्स कॉर्प में हैं। पिछले सात सालों के इनके संगठन द्वारा किए गए संघर्षों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद का चार फीसदी दलित कारोबारियों से खरीदने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्रों के बड़े औद्योगिक घरानों ने भी डिक्की की इस पहल का स्वागत किया है। टाटा मोटर्स ने भी दलित कारोबारियों से खरीदारी का फैसला लिया है। जाहिर है कि डिक्की के इस पहल से दलित कारोबारियों को आम कारोबारियों के साथ पूंजी का साम्राज्य खड़ा करने का मौका तो मिलेगा लेकिन इससे वंचित दलित समुदाय के हिस्से को कितना फायदा मिल पाएगा, यह तो भविष्य में ही पता चल सकेगा।

दलित चिंतक उदित राज का इन दलित उद्योगपतियों के विपरीत यह मानना है कि दलित समाज को मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए अभी भी कम–से–कम 50–100 वर्ष आरक्षण की जरूरत है। वे डिक्की के सदस्यों द्वारा आरक्षण का विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर तल्खी से भरकर कहते हैं, 'डिक्की से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनके सदस्यों द्वारा आरक्षण का विरोध किए जाने की बात नहीं पचती है। वे मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। सारे दलित कारोबारियों की कुल संपत्ति कुछ मझोले कद के सवर्ण उद्योगपतियों के पूंजी के बराबर भी नहीं होगी। बड़े शहर की किसी एक अमीरों की कॉलोनी में जितने सवर्ण पूंजीपति रहते हैं, उतने पूरे देश में दलित एवं आदिवासी व्यापारी नहीं होगे।

DICCI
Developing Business Leadership

गणतंत्र दिवस मनाते हुए पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण पर संघर्ष जारी

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज ने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस में भाग तो लिया गया लेकिन दूसरी तरफ आक्रोश भी देश में जगह–जगह पर व्यक्त किए गए कि हमारी पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग अभी तक पूरा नहीं हो पायी है। ऐसे अवसरों पर एहसास कराना विशेष महत्त्व रखता है। यह भी आवाज उठी कि क्यों नहीं डॉ0 अम्बेडकर को इस अवसर पर दिखाया या बताया जाता? आन्ध्र प्रदेश परिसंघ के अध्यक्ष, के. महेश्वर राज के नेतृत्व में इस आवाहन को अंजाम सबसे जोरदार तरीके से दिया गया, वहां की राजधानी हैदराबाद में लोग एकत्रित हुए और अपनी आवाज बुलंद की। देश के अन्य भागों में भी ऐसा किया गया है, लेकिन सूचनाएं वांक्षित हैं।

Unity of Dalit, Advasi and Backward Students is Paramount

Harshvardhan Dawne

For thousands of years, the upper caste people have deprived Dalits, Adivasis and the Backwards from education, participation in governance and a place of pride. Even when these people managed surreptitiously to acquire knowledge and skill, their thumbs were cut or they were beheaded. Even the God of this upper caste civilization beheaded a Dalit while he was worshipping. Had the Britishers not come to India, then perhaps the doors to the halls of education would have remained closed. A great person like Jyotibaphule did not only fight for the education of Dalits, Adivasis and the Backwards but also fought for the rights of women. Dr. Ambedkar attached maximum importance to the cause of education and urged the people to become educated, be united and struggle. Without education, man is like an animal. From this, it is not difficult to make out as to how for centuries, Dalits, Adivasis and Backwards were treated as animals. Now this situation is no more acceptable to us and the right to education is our priorioty. We even go to the extent of saying that we are ready to go without food but to live without education is worse than death.

Dalit and Adivasi students and youthts have particularly so much become victims privatization and liberalization that even after getting higher education, they are unsuccessful. One of the reasons for the education of Dalits and Adivasis is that because of reservation, they used to get jobs. In 2000, the total number of Dalits and Adivasis in Government jobs was about 40 lakh but according to the present estimates, this number is reduced to about 278 lakh and it is going to reduce further in the days to come. The number of jobs in the private sector has tremendously increased but we cannot get employment in the private sector, howsoever we may become educated, because commerce and trade are mostly in the hands of the upper caste people. The All India Confederation of lSC/ST Organizations, under the leadership of Dr. Udit Raj, has been struggling relentlessly for the last ten years for reservation in the private sector but the paradox is that the students of these communities are hardly aware of the struggle what to talk of their participation in this struggle.Privatization has affected nearly all the sectors. Now, mostly the students studying in Government schools and institutions belong to SC/ST category because the upper caste people have created better educational facilities and institutions for their children. Because of the money power, children of the upper castes are going abroad also.Thus the SC/ST people are being doubly victimized.

Because of the campaign launched by the All India Confederation of SC/ST Organizations, the Central Government in the year 2004 had announced a Minimum Common Programme in which, among other things, there was the promise of reservation in private sectors. For this purpose, a coordination committee was constituted and a committee of the officers of the Commerce Ministry was constituted in 2008 but so far, there has been no progress on this issue.Prominent organizations of the Corporate houses like C.I.I, FICCI and ASSOCHAM etc have opposed reservation in private sector by saying that they will suitable steps in this regard on their own but it is an eye wash. If reservation in private sector become a reality, the benefit of the same will go to students and youths of the country and not employees and officers of the Confederation. In the present scenario, the circumstances are such that if there is no reservation in private sector, education will cease to have any meaning for SC/ST people. Leaving aside Maharashtra, there is no other State where SC/ST students and youths are struggling for this cause, rather they hardly know the work being done by the Confederation in this regard. Even the hostels made earlier for SC/ST students are not being maintained properly and no efforts are being made to construct new hostels. There has been no increase in the scholarship amount in proportion to hike in fees and cost of living. We cannot get admission to private educational institutions due to the lack of reservation in seats for SC/ST students. If somehow the SC/ST parents are able to send their children for higher education, they can do so only at the cost of falling into the debt-trap. Wherever there is reservation in the private sector, the amount of the Govt. scholarships is very meager and 70% of the cost of education has to be borne by such students themselves and thus they are ultimately deprived of education.

Firstly, we have taken up the cause of Dalits and Adivasi students and youths but that does not mean that we do not want to struggle for the rights of the backward categories of people.When the backward category people got reservation in institutions of higher learning in the year 2006, it was opposed by the upper caste people. Dalits came forward and struggled for the cause of the backward people but the backwards themselves did nothing. Under the leadership of Dr. Udit Raj, the cause of the backwards was taken upon different platforms and the AIIMS which had become a hot-bed of anti-reservation activities, was gheraoed which gave a great jolt to the activities of the anti-reservation front. When the V.P. Singh Government announced the implementation of the recommendations of the Mandal Commission, there was maximum opposition from the backward people and the first student who immolated himself belonged to the backward category. It is also a matter of fact that there is not sufficient awareness of the thoughts and ideologies of thinkers like Ambedkar, Phule, Sahu etc. Due to this reason, there is not sufficient urge among backwards for fighting for their rights. We also want their whole-hearted support but if their cooperation is nominal, it would be difficult to achieve their goals. Population of the backwards is 52% and even if 10% of them, stand by us, we shall be happy.Their indifference can be gauged from the fact that in the year 2002, they got 27% reservation but so far they have availed only 6% quota. It is mostly Dalits who fight for their rights.

We firmly stand for unity and integrity of the country, not only in letter but in spirit. Other student organizations also talk about unity and integrity of the country but without participation in governance and society. We were slaves for 2000 years because participation was not there for all castes and groups and participation in the governance of every sector alone can make India a world power. We want participation in all the fields like journalism, armed forces, higher judiciary, films, sports in proportion to their population. This will not only empower them socially, politically and economically but will create overall prosperity and peace in the country.

Media with the Manuwadi mindset does not publish our viewpoints. Due to a revolution in scientific innovations cheap media gadgets like internet, facewbook, tweeter, blog, SMS, mobile phones, miss calls etc are not available. Anna Hazare made ample use of these gadgets in his campaign "India Against Corruption". A country-wide struggle was launched on the Nirbhaya rape and murder case because of this social media. We will have to launch a struggle for our rights which should be ten times stronger that upper caste students and youths and it will be our endeavour that in 2013, to unite about one lakh SC/ST students and youths.If we cannot do even this much then we should forget that we shall ever be able to launch a struggle for getting participation in governance. If Anna Hazare has been able to unite lakhs of people in a couple of days through social media, then why we cannot unite more number of people in one uyear.

Dalits and Adivasis students!If we do not reservation in private sector, there will be mis-rule of Manusmriti.

Contact-07709975562

... Rest of Page-8

Caste and Corruption

here so called intellectuals take note of changes once it is already occurred . Our society is least influenced by their writings, speeches, talk and thoughts. After all, Ashish Nandy is a product of this social background and nothing big can be expected from him.

Ashish Nandi has said that corruption is relatively less in West Bengal and for which he has given the credit to Left Front and upper caste people. He has also said that no prominent leader has emerged from amongst Dalits, Adivasis and Backwards in the last 100 years in West Bengal and thus the economic corruption has been less but the social corruption has been on the higher side. It would also have been good for Dalits, Adivasis and Backwards if economic corruption would been there in West Bengal as much as it has been there elsewhere provided they had also been part and parcel of the governance process. The issue of participation in the governance process is more important than economic corruption. The Left Front may not accept this fact but it is a stark reality. The Left front was wiped out because they refused to acknowledge this fact otherwise there was no reason why it should not have been successful in India like Russia where Marxism flourished. So far the charge levelled against the Left that are extremely pro-Brahmin, is true. Ashish Nandy's statement confirms this view-point. How is it possible that a State where the population of Dalits, Adivasis and Backwards is 80%, is not able to produce a leader of their own? Shall we take it that they are fools and incompetent?

Just as Anna Hazare's campaign "India Against Corruption" gained momentum across the country, there should be a debate as to which caste is corrupt and which is not. Debate will add a large perspective to the issue and the castes which are corrupt will be exposed and it will exert psychological and mental pressure on them which might result in reduction in corruption. In our country, things move faster due to competition and ego. When the ego of the people belonging to a particular caste is hurt, they will hesitate from indulging in corruption. A few days ago, a conference was held in N.D.Tiwari Hall, New Delhi , where I happened to meet Anna Hazare. I told him that as compared to the previous year, there has been an increase in corruption and thus there has been no gain or benefit from the indefinite fast undertaken by him. In reply, he said that the campaign against corruption will have to be launched at the village level. I further told him that there are more than 6 lakh villages in India and it will take thousands of years to wipe out corruption in this way as he has spent his life-time in improving the conditions of just one village. Most of the people are advocating that corruption cannot be attributed to the people of any specific caste but it is not a fact. The foundation of our caste system and social structure is based on falsehood and lie telling. Economic corruption is child of lie telling and this has been since ages. High and low positions in life are God's will and the society is based on this dogma. Is it true? A falsehood is an act of corruption by itself. Struggle against economic corruption will not be successful till intellectual corruption is weeded out. It is an established fact that if debate takes place on a national level on the issues of caste and corruption, it will yield good results.

All India Confederation of SC/ST Organisations, A.P State Unit Celelbrated 64th Republic Day & Constitution Enactment Day

K. Maheshwar Raj

All India Confederation Of SC/ST Organisations, A.P State Unit celebrated 64th Republic Day & Constitution Enactment Day on 26.01.2013 by hoisting National Flag at Ambedkar Statue, Tank Bund, Hyderabad. Around 200 Members belonging to SC/ST/OBC/Minorities categories from State & Central Government Departments participated in the Celebrations.

The Programme started with Boudha Vandan by Shri B.Bodhinath.

Speaking on the occasion, Shri K.Maheshwar Raj, AP State President, AICSO, told that they had celebrated this historical event at Ambedkar Statue because Bharat Ratna Baba Saheb Dr.B.R.Ambedkar is the Architect of Constitution of India. Dr. BR Ambedkar played a pivotal role in Enactment of Constitution which declared India as a Republic and India became a sovereign country in the comity of nations. Under the banner of All India Confederation of SC/ST Oragnisations, AP State Unit, all Employees' Associations, Dalit Activists and SC/ST Organisations, who support the Confedration strongly demanded Reservation In Promotions & Reservation In Private Sector.

Later, he told that recently, in the National Capital, New Delhi, Confederation's National Chairman Dr.Udit Raj, had organised a MAHA RALLY at Ramlila Maidan demanding Reservation In Private Sector & Higher Judiciary . He strongly urged the Government to re-introduce the 117th Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha for reservation in promotions. All Political Parties and all Members of Parliament were requested to support the Bill in the Parliament.

He declared that the Confederation was going to organise a MAHA RALLY at Hyderabad during the coming Parliament Budget Session to achieve our major demands. The Confederation thanked Deputy Chief Minister Shri C.Damodar Raja Narsimha, Ministers Smt. Geeta Reddy, Shri Kaki Madhava Rao, former Chief Secretary, Shri Mallepalli Laxmaiah, Sr.Journalist and all who worked for getting the SC/ST Sub-Plan on 25.01.2013. Lastly K.Maheshwar Raj told that the Confederation highly appreciated Hon'ble Member of Parliament Shri Asaduddin Owaisi for the tributes paid to Dr. B.R Ambedkar for his relentless struggle and contribution to India becoming a Republic . He also praised Shri Asaduddin Owaisi as one of the True Indians, who expressed his faith in Indian Judiciary. Confederation welcomed the call given by Owaisi for working collectively with SCs and STs in future.

Further, Gaddar, the Revolotionary Balladeer has demanded that Reservation in Promotions Bill should be passed in the forthcoming Budget Session. He reminded that Congress Government was in the habit of decieiving Dalits with their unfulfilled promises. All Ruling Parties were doing injustice to Dalits all over India since decades and demanded that Government should address the problems of Dalits with sincereity and honesty. Shri J.B Raju, Senior Dalit Leader appreciated the Confederation activities and hoped that the Maha Rally would be a grand success and create a history in Andhra Pradesh Dalit Movements.

S/Shri S.Rama Krishna, YM Vijay Kumar, S.Gouri Shanker, B.Narsing Rao, K.Nageshwar Rao, Gali Vinod Kumar, P.Suresh Kumar, BV Vinod participated in the deliberations.

... Rest of Page-8

Dr. Udit Raj's Birthday Celebrated With Great Fanfare As Justice Day

Karawal Nagar Constituencies respectively for the forthcoming Delhi State Assembly. Dr. Udit Raj said that Ch. Ravinder Singh started his career by joining Uttar Pradesh Police but he could not tolerate the rampant corruption atrocities being committed by UP Police on Dalits and downtrodden sections of the society and in sheer desperation resigned from UP Police Force. After that he joined R.S.S. but got fed up with their communal politics and resigned from there also. At present, he is doing social work as a member of the Gurjar Samaj Sudhar Samiti and DLF Sudhar Samiti. It is because of his commitment to this noble cause, he has been appointed as the President of Delhi Unit of the Indian Justice Party and after seeing the large crowds at this function, it has been found that there cannot be a better person than him as a candidate for the Mustafabad Assembly constitutencyk. Dr. Udit Raj also said that Shri Jitender Bansal, B.Ed., has got four years experience of working in the Congress Party. After that resigning from that party, he joined Bahujan Samaj Party but after seeing the fascist attitude of Ms Mayawati, he left this party also just after one year and at present he working with the Shiksha Sudhar Samiti. The credit for conveying the message of education and justice for all which are the core principles of the Indian Justice Party to Shri Jitender Bansal goes to Master Inderjit Singh. It was because of the commitment of Shri Bansal that he was made the District President of the Party for North East Delhi and now he is being nominated as the party candidate for the Karawal Nagar Assembly seat for the forthcoming elections.

On this occasion, Dr. Udit Raj heartily greated the huge gathering and thanked all the leaders of the Indian Justice Party who had played a prominent role in organizing this grand function. He further said that he would take it as the greatest gift if the people present on this occasion take a pledge to fight against casteism, corruption etc. He said that normally role models of the common people are those who are successful in life from whom they can get some benefits but he believed that everybody has the inmherent talent and energy to succeed in life provided they should recognize their potential and make constructive use of the same.

While addressing the gathering, Shri Indresh Gajbhiye, Minister in the Madhya Pradesh Government and National President of Dr. Ambedkar Parinirvan Karyakram Samiti, said that the post of a Minister is like a ringlet in the feet of a dansuse which can be tied or untied at any time, but like Dr. Udit Raj and all of you who are engaged in welfare of the socielty will be remembers for ever. Whatever money an industrialist may earn during his life time but quite often it so happens that there are few people even from amongst his relatives to perform the last rites at the time of his death and this job is done by his staff members but people who are engaged in the welfare of the society are always liked by the society in the long.

Shri Suresh Diwan, Incharge of Delhi Pradesh Unit of the Indian Justice Party who was also the anchor of the function, said on the the occasion that the Delhi Unit has been celebarating the birth day of Dr. Udit Raj right from the inception of thje party and this occasion is celebrated as Justice Day. This year's event is being celebrated in the State Assembly constitutency of Ch. Ravinder Singh from where he is bound to win.

Shri Parmender, National General Secretary of the Indian Justice Party and Shri Sanjay Raj, National Coordinator of the Youth Wing of the Indian Justice Party congratulated Dr. Udit Raj on the occasion of his birthday.

Ch. Ravinder Singh, State President of Delhi Unit of the Indian Justice Party, reiterated his resolve in the presence of Dr. Udit Raj and other leaders of the party that he would continue to work ceaseless for the principles of the Party throughout his life and with the cooperation of all concerned, he would do his best to win the Delhi State Assembly elections. He thanked all the guests to take part in the function in his Assembly constitutency.

Master Inderjit Singh, State General Secretary of Delhi Unit of the party, said that the cardinal principle of the party is to establish a classless society with equal and compulsory educal for all. Government has enforced law for Right to Education but the children of Dalits and other downtrodden sections of the society study in Government schools where the standard of education is going down continuously whereas public schools are running quite .efficiently with much less resources . It is beyond the reach of the poor and downtrodden sections of the society to send their children to private schools. It is our firm conviction that till equal education is provided to all, children of Dalits and the downtrodden sections of the society will continue to be at a great disadvantage. We are celebrating this occasion as a Justice Day which is symbolic of justice for all and on this day, we take a pledge to work ceaselessly for classless society with equal and compulsory education for all .

Shri Jitender Bansal, District President, North East Delhi, Indian Justice Party, assured Dr. Udit Raj that he would do his utmost to win the Karawal Nagar Assembly seat. For this purpose, he would go from door to door and constitute committees at the booth level.

While addressing the gathering, Shri Vinod Kumar, National General Secretary of the All India Confederation of the SC/ST Organizations also congratulated Dr. Udit Raj on his birthday.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 5 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 January, 2013

इच्छा ही सब दुःखों का मूल है।

-गौतम बुद्ध

Dr. Udit Raj's Birthday Celebrated With Great Fanfare As Justice Day

Dr. Udit Raj

Birthday of Dr. Udit Raj, National President of the Indian Justice was celebrated with great fanfare as "Justice Day". This function was organized by the office bearers of Delhi Unit of the Indian Justice Party, namely, Shri Suresh Diwan, Incharge, , Ch. Ravinder Singh, President,, Shri Inderjit Singh, General Secretary, Shri Kali Charan Netaji, Secretary, Shri Prem Chand Prajapati, Secretary, Shri Jitender Bansal, District President, North East Delhi, all from Delhi Unit of the Party at Mayur Garden, Karawal Nagar, Delhi. People from different parts of Delhi started coming coming to the birthday venue from 11 AM onwards and in a short span of time, a huge crowd had gathered at the birthday venue. Dr. Udit Raj along with his wife, Smt Seema Raj, their son, Abhiraj and daughter Saveri and other close relatives reached the venue at about 1 PM and were greeted by the crowd clappings and slogans like Dr. Udit Raj Zindabad and hundreds of people from the Gurjar Samaj and dignitaries and people from different communities extended their hearty greetings to them. The prominent among these people were Sarv Shri Ch. Narendar Singh, Ch. Balkishan, Ch. Ravinder Singh, Ch. Jitender Bansal, Ch. Dharmender Singh, Shri Room Ram Mahaur, Shri Devender Balmiki, Shri Prem Chand Prajapati,Shri Kali Charan Netaji, Shri Brahmpal Kashyap, Thakur Devender Singh, Shri Satish Chand Sharma, Shri Suresh Diwakar, Shri Lav Kush and Shri R.A.Yadav etc.

While addressing the gathering, Dr. Udit Raj, National President of the Indian Justice Party announced amidst thunderous clappings the announced the nomination of the names of Ch. Ravinder Singh and Shri Jitender Bansal as candidates of Indian Justice Party from Mustafabad and

Rest on Page-7...

Dr. Udit Raj cutting the cake along with his wife Seema Raj

From left: Dr. Udit Raj, Ch. Ravinder Singh & Shri Jitender Bansal on the dais.

Huge crowd on Dr. Udit Raj's Birthday

Caste and Corruption

Dr. Udit Raj

On the occasion of the Republic Day, during the Jaipur Literary Festival, Ashish Nandi, a social thinker, made a statement that Dalits, Adivasis and Backwards are involved in most of the corruption cases. This statement has different interpretation and implications. Undoubtedly, this statement shows these groups in a bad light and is condemnable but it has other aspects also and if a country-wide debate is held on this issue, the campaign against to fight the corruption will get further intensified.In our county, nothing is more powerful and perennial than the caste factor. Till death, one cannot get rid of the caste tag. Even if someone leaves India and goes to a foreign country, the caste paraphernalia travels with the individual. All sorts of comments are pouring on the statement of the Ashish Nandy. Some people are saying that corruption does not belong to any particular caste while some others are giving the plea that statement should be read in full context. There is a demand for the arrest of Ashish Nandy. Whatever he has said on this issue, can not be retracted but if an intensive country-wide debate on the corruption issue takes place which caste is more corrupt, as it has happened in the Nirbhaya rape and murder case, some positive results are bound to come.

It is wrong to say that that Dalits and Adivasis are the more corrupt. Last year, Government of India disclosed the names of 17 people with foreign accounts out of whom, not a single foreign account-holder belonged to Dalit or Adivasi category. In the Jain Hawala scam also, there was no Dalit or Adivasi. Lakhs and crores of rupees of Indian money is lying in foreign banks. It is very likely that here also, no Dalit or Adivasi is involved. None of the scamsters like Harshad Mehta, Ketan Parikh and Telagi are Dalits or Adivasis. There was about 70,000 crore fraud in the Commonwealth Games. Government was duped of Rs. 44,000 crore in the Kaveri Gas case. Coal Block Distribution scam is known to one and all. None of the 2G spectrum licensees belonged to Dalit category. Of course, the Minister concerned from Dalit category. It may not be wrong to say that if any Dalits and Adivasis are at all corrupt, it may be an exception rather than a rule. The number of corrupt people belonging to OBC category could be a little more but in comparison to their population, it will also be very negligible. If an opposite interpretation of Ashish Nandy's statement is taken, it will become an established fact that the upper castes are more corrupt than Dalits and Adivasis.

The caste which exercises control over the political, religious, social and economic power, gives birth to other institutions also. Corruption has become an established institution in our country. After Independence, the strings of the Executive, Legislature and Judiciary are in the hands of the upper caste people and it can be safely said that the foundations of corruption were also laid at that time. The ruling class is always the originator of institutions, traditions and customs of the society. Maximum corruption in our country takes place in the name of religion. Cash, Prasad, chadars, gold and silver ornaments, cocks and goats etc. offered to Deities is nothing short of corruption. It can be said without any doubt that the upper caste people have laid the foundations for corruption in the country and for the last some decades, Dalits, Adivasis and Backwards have been influenced by this social evil. The real culprit is the originator caste which has given birth to corruption. Thus, Ashish Nandy should do an introspection of his statement and he will find that the opposite of his statement is correct. Most of the intellectuals in our society are not mentally honest and at the same time they have no connect with reality. A man does not become an intellectual just by becoming a book-worm. Unlike Europe and America,

Rest on Page-6...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by N. K. Karn